THE VICE-CHAIRMAN (SHRI T.N. CHATURVEDI): That is all right ...*(Interruptions)*...

SHRI ARUN JAITLEY: Sir, may I suggest before I formally move the Bill, because I think amongst all these legislations, this, perhaps, is the most important one. It has taken the Indian Parliament to come to a consensus and the various connected people to agree to this reform a period as long as 50 years. Therefore, it is important that we pass this Bill in this Session in both the Houses. Since I have only five days thereafter left in the next week for this Session -- and if you keep the Fridays out, this period will be only four days -- my request would be that this Bill is passed this week itself so that I am able to take it to the Lok Sabha next week for its approval.

SHRI PRANAB MUKHERJEE: We will past it on Monday. ...*(Interruptions)*... You will get it. ...*(Interruptions)*...

SHRI ARUN JAITLEY: May I suggest because it is not a Bill which is going to involve a very long debate because most of the items have unanimous recommendation of the Standing Committee, we can, if Members agree, sit for half-an-hour or one hour, depending on what the Members feel ..*(Interruptions)*... Or we can sit after the Private Members' Business.

SHRI PRANAB MUKHERJEE: I assure the hon. Minister that we will take it up on Monday. There will be no problem. He will have Tuesday, Wednesday and Thursday to get it passed in the Lok Sabha.

SHRI ARUN JAITLEY: Sir, then I will just move the Bill. ...*(Interruptions)*...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI T.N. CHATURVEDI): You can move it. ...*(Interruptions)*...

THE INDIAN DIVORCE (AMENDMENT) BILL, 2000

THE MINISTER OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS AND THE MINISTER OF SHIPPING (SHRI ARUN JAITLEY): Sir, I move:

> "That the Bill further to amend the Indian Divorce Act, 1869 be taken into consideration."

The question was proposed

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI T.N. CHATURVEDI): Would you like to make any speech? ...*(Interruptions)*... It will be taken up for consideration later on. ...*(Interruptions)*... All right. Now there is a statement by the Minister regarding Basmati.

STATEMENT BY MINISTER

Patent on Basmati Ricelines and grains to Ricetec Inc. USA.

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. रमण) : उपसभाध्यक्ष महोदय, दिनांक 21 अगस्त, 2001 को मीडिया रिपोर्टों के आधार पर माननीय सदस्यों और अन्य व्यक्तियों में यह आभास कराया गया है कि एक अमेरिकी फर्म ने बासमती चावल पर पेटेंट प्राप्त कर लिया है और इस कार्रवाई से भारत के बासमती चावल के व्यापार/निर्यातों के संबंध में बुरा तथा प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। ऐसा भी आभास कराया गया है कि भारत उक्त पेटेंट में संशोधन किए जाने हेतु संयुक्त राज्य पेटेंट तथा ट्रेड मार्क कार्यालय (यू.एस.पी.टी.ओ.) के सम्मुख अपना मामला "हार" गया है।

प्रारंभिक रूप में मैं सदन को निश्चित रूप से सूचित करना चाहूंगा कि ये रिपोर्टें गलत हैं और ये गलत धारणा पर आधारित हैं। वास्तव में उक्त पेटेंट के संबंध में यू.एस.पी.टी.ओ. का निर्णय भारत के लिए एक विजय का संकेत देता है। माननीय सदस्यों ने दिनांक 22 अगस्त, 2001 की बाद में छपी प्रेस रिपोर्टों को भी पढ़ा होगा, जिन्होंने पूर्व के भ्रांतिपूर्ण प्रभाव को ठीक कर दिया है। इस संबंध में तथ्य निम्न प्रकार हैं :-

बासमती राइस लाइन्स और खाद्यान्नों पर एक पेटेंट 2 सितम्बर, 1997 को यू.एस.पी.टी.ओ. द्वारा मै राइस टैक इंक., यू.एस.ए. को प्रदान किया गया था। इसके लिए एक आवेदन 8 जुलाई, 1994 को दायर किया गया था। पेटेंट पर 20 क्लेम थे।

यू.एस.पी.टी.ओ. के हाल ही के निर्णय के बाद, 15 क्लेमों को पहले ही रद्द कर दिया गया है और शेष 5 क्लेम भारत में उत्पादित बासमती की किस्मों को प्रभावित नहीं करते हैं और ये भारत के व्यापार / निर्यातों पर भी प्रभाव नहीं डालेंगे। वास्तव में पेटेंट का शीर्षक जो "बासमती राइसलाइन्स और ग्रेन्स" था, भी बदलकर अब "राइसलाइन्स बास 867 आर0टी0 1117 और 1121" कर दिया गया है। अत: अमेरिकी कंपनी इन तीन राइसलाइनों पर पेटेंट तक ही सीमित है, जो कि इसने विकसित किए हैं।

उक्त पेटेंट की मंजूरी से आमतौर पर भारत के निर्यातों को और खासतौर पर यू.एस.ए. को किये जाने वाले निर्यातों को प्रभावित नहीं किया है। वास्तव में, बासमती